श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति,
राजस्थान का उद्‌बोधन

कोविड–19 की पृष्ठभूमि में जनजाति क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समग्र संवाद

दिनांक 21 अप्रेल, 2020 **समय दोपहर : 01.15 बजे**

स्थान : राजभवन, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, संभागीय आयुक्त, उदयपुर, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, कलक्टरगण एवं अन्य अधिकारीबन्धु। कोविड–19 की महामारी की पृष्ठभूमि में हम सब यहा एक सार्थक चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए है।

राजस्थान का जनजाति क्षेत्र अत्यन्त पिछडा है। अतः इस लॉकडाउन में इस क्षेत्र के लोगों को, खासकर जनजाति मूल के लोगों के लिए अत्यधिक जागरुक होने की आवश्यकता है।

सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जनजाति क्षेत्रों में कोविड–19 का प्रसार काफी कम हुआ है, केवल बाँसवाडा के कुशलगढ पंचायत समिति क्षेत्र में कोविड–19 के 60 व्यक्ति पॉजिटिव चिन्हित पाये गये है, जबकि अन्य जनजाति जिलों में यह संख्या 5 या उससे कम है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि आपको कम संख्या के कारण अभी निश्चिंत नहीं होना है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक सक्रंमित व्यक्ति कई लोगों तक यह बीमारी पहुँचा सकता है।

जयपुर, टोंक, कोटा एवं जोधपुर इसके ज्वलंत उदाहरण है। सबसे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि उक्त महामारी के मद्देनजर आपने अपने जिलें में

कौन–कौन से नवाचार किये है। आपके नवाचारों से अन्य जिलें एवं सम्पूर्ण राजस्थान इस बीमारी के प्रसार को रोक सकते है।

जैसा की आपको विदित है जनजाति क्षेत्रों के मजदूर/श्रमिक बडी संख्या में नजदीकी प्रदेशों में रोजगार के लिये पलायन करते है। लॉकडाउन के कारण इन सभी प्रवासी मजदूरों को आजीविका संधारण में विकट समस्या आ गई है। ज्यादातर मजदूर/श्रमिक पड़ोसी राज्यों के केम्पों में रह रहे है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि इन प्रवासी श्रमिकों के लिये आपके द्वारा क्या प्रयास किये गये है। इसके अतिक्ति जनजाति क्षेत्रों में काफी संख्या श्रमिक प्रतिदिन की आय पर अपना जीविकोपार्जन करते है अर्थात ''रोज कमाने एवं रोज खाने की पद्धति'' से आजीविका संधारण करते है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके लोगो ने ऐसे गरीब/अकुशल श्रमिकों के लिये क्या–क्या व्यवस्था की है।

जनजाति क्षेत्रों में कई योजनाएं संचालित है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे जनजाति भाईयों के लिए यदि किसी योजना में उनके खाते तक तुरन्त पैसे पहुँचाये जा सकते है और इसे आप **DBT**

(Direct benefit Transfer) के प्रारुप में क्रियान्वित कर सके तो इनकों काफी राहत दी जा सकती है।

जैसा की आपको विदित है कि बडी संख्या में जनजाति छात्र आश्रम छात्रावासों में रहकर अध्ययन करते है। लॉकडाउन की स्थिति में मुझे यह लगता है कि उन छात्रों को शिक्षा से जोडे जाने के लिये ऑन लाईन मोड पर पहल करनी पडेगी। व्हाटसप ग्रुप, जूम क्लासेज अथवा अन्य नवाचार करते हुए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्था से जुडे रहे।

वर्तमान में रबी की फसलों की कटाई चल रही है एवं कइ जगह इनकी कटाई पूरी हो चुकी है, राज्यों एवं केन्द्र सरकार की एडवाईजरी में यह स्पष्ट कहा गया है कि फसल कटाई की मशीनों को ना रोका जाये एवं जिला कलक्टर्स द्वारा किसानो की फसलों के विक्रय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि मनरेगा के तहत 20 अप्रेल के उपरांत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप सोशल डिस्टेंशिंग का ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मजदूर नियोजित किये जाये ताकि उन्हे आजिविका के साधन गॉव में ही उपलब्ध कराये जा सके।

मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आपके नवाचारों के बारे में सुनना, समझना एवं सीखना भी चाहता हूँ। मेरे विचार से यह एक महायुद्ध है एवं हम सब को अपने मन, वचन, कर्म से समर्पित होकर गरीब को गणेश मानकर सेवा करनी चाहिए।

यह एक ऐसा मौका है जिसमें ईश्वर ने हम सब को अपने अच्छे कर्मो को बाहर लाने का अवसर दिया है। मुझे आशा ही नही अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे बाकि आपकी बात सुनने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ।

धन्यवाद। जय हिन्द।